(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether this expansion of ties will help India in improving its position in commercial and industrial sectors; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (d) Under the broad framework of an agreement for economic and commercial cooperation between India and the EEC efforts are constantly made to diversify and expand bilateral ties. The framework of cooperation now includes not only commercial relations but industrial cooperation and for science and technology. Activities and programmes mutually taken up in the new areas of cooperation are expected to help develop some of the essential infrastructural support by way of technology data bank, quality control mechanism and research and development projects in Air Pollution Monitoring and Immunology and Immunoprophylaxis of leprosy, etc.

टिहरी बांध परियोजना के संबंध में प्रदूषण के पहलू पर एस० के० राय समिति का प्रतिवेदन

840. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री रशीद मसूद :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध परियोजना के संबंध में प्रदूषण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये श्री एस. के. राय की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने इस कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखे बिना ही इस परियोजना की स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सोवियत संघ के विशेषज्ञों से भी प्रदूषण के इस प्रश्न का अध्ययन करवाया गया था; यदि हां, तो उस अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख) श्री सुनील के. राय की अध्यक्षता में 1980 में गठित कार्यकारी दल ने टिहरी बांध परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की जांच की।

परियोजना को 1972 में तकनीकी आर्थिक मंजूरी पहले ही दे दी गई थी इसलिए फिर से मंजूरी की कोई जरूरत नहीं थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एम० एम० टी० सी० द्वारा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ पक्षपात

841. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री रशीद मसूद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1988 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एम.एम.टी.सी. फेवर टू मल्टी नेशनल्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एम.एम.टी.सी.एन.ए.एल.सी. ओ. को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किए गए कुछ सौदों में निरर्थक ही हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में [illegible]